Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

मार्च 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष 3
- उत्तराखंड में नई हेली सेवा का उद्घाटन 3
- उत्तराखंड में बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ 4
- जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध 5
- उत्तराखंड हिमालय में तेज़ी से बढ़ती हिमनदीय झील को लेकर चिंताएँ 6
- उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भारत द्वारा सैनिकों की तैनाती पर विचार 7
- उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा की तैयारी के लिये समिति का गठन 8
- उत्तराखंड ने 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू कीं 9
- उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिये सैकड़ों लोग आगे आए 9
- उत्तराखंड ने रोज़गारोन्मुख उद्योगों के लिये सब्सिडी की घोषणा की 11
- एशियाई विकास बैंक ने टिहरी में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण को स्वीकृति दी 12
- उत्तराखंड में UCC को राष्ट्रपति की मंज़ूरी 13
- गरतांग गली 14
- उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी 15
- उत्तराखंड ने गोपेश्वर में विकास योजनाएँ शुरू कीं 15
- उत्तराखंड के मोटे अनाज के किसानों की आय में वृद्धि: अध्ययन 16
- उत्तराखंड में बुनियादी ढाँचे के विकास को स्वीकृति 17
- दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का गृह सचिव नियुक्त किया 17
- अधिकारियों ने जोशीमठ में सरकारी भवनों को रेड ज़ोन से स्थानांतरित करने को कहा 18
- उत्तराखंड में ग्लोबल फेस्ट में 700 से अधिक योग विशेषज्ञों ने भाग लिया 19
- उत्तराखंड की उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन 20
- उत्तराखंड चार बाघों को राजस्थान स्थानांतरित करेगा 21
- भारतीय रेलवे और उत्तराखंड पर्यटन ने लॉन्च की मानसखंड एक्सप्रेस 21

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष

चर्चा में क्यों ?

राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक हिमालयी राज्य में 444 लोग मानव-वन्यजीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं।

मुख्य बिंदु:

- पीड़ितों को मारने वाले जानवरों में तेंदुए, बाघ, भालू, साँप, हाथियों और तेंदुए शामिल थे।
- पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को कुल 21.3 करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं।
- पीड़ितों के लिये मुआवज़ा राशि बढ़ाने के अलावा, यह पहली बार है कि राज्य ने मधुमक्खी, हॉर्नेट (तेज़ डंक मारने वाला भिंड), बंदर और लंगूर द्वारा हमला किये गए लोगों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया है।
    - अनुग्रह भुगतान वह धनराशि है जो नैतिक दायित्व के कारण भुगतान किया जाता है न कि कानूनी दायित्व के कारण।

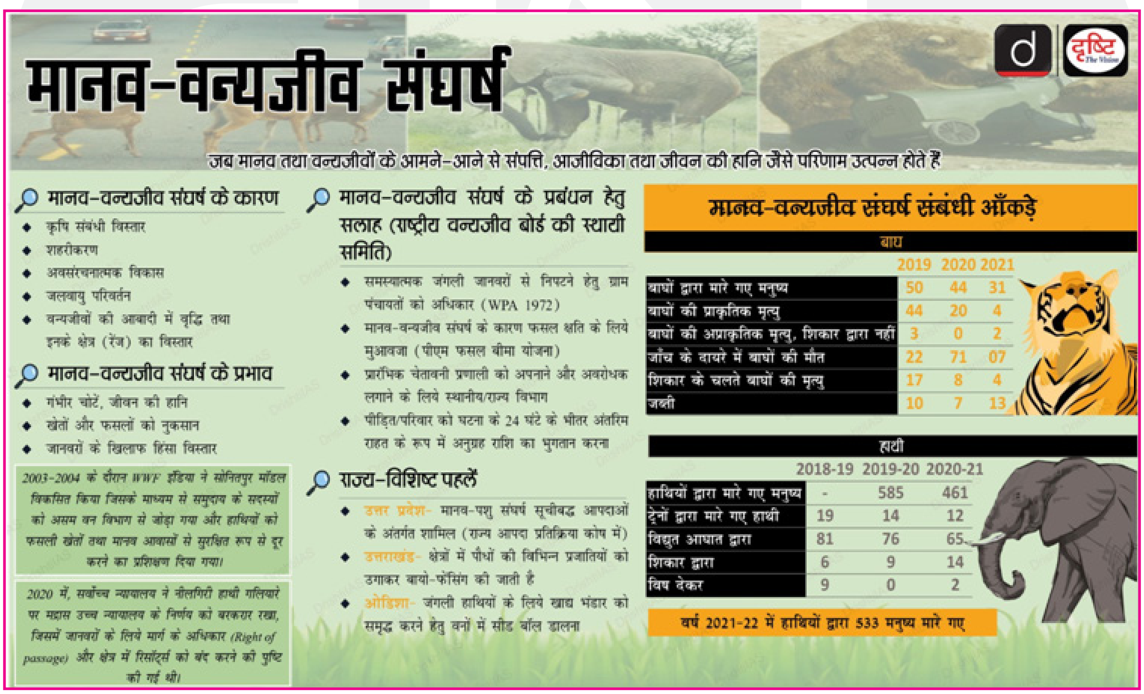

उत्तराखंड में नई हेली सेवा का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड में हेली सेवा का उद्घाटन किया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- नई शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा हलद्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ और चंपावत से जोड़ेगी।
- यह पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य इन दूरदराज़ के क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करना है।
    - उत्तराखंड के चुनौतीपूर्ण इलाकों के कारण, हवाई कनेक्टिविटी रोज़मर्रा की यात्रा और महत्त्वपूर्ण आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं दोनों में सहायता करेगी।
- यह लॉन्च हाल ही में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद हुआ है।
- आगामी हवाई मार्गों की भी घोषणा की गई, जिनमें देहरादून से अमृतसर, देहरादून से पंतनगर और देहरादून से अयोध्या शामिल हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना: उड़ान

- **परिचय:**
    - क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) लॉन्च किया गया था।
    - यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 का एक हिस्सा है।
    - यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- **चरण:**
    - चरण 1 को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में अनुपयोगी और असेवित हवाईअड्डे को शुरू करना था।
    - चरण 2 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के अधिक दूरस्थ और दुर्गम हिस्सों में हवाई संपर्क का विस्तार करना था।
    - चरण 3 को नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देश के पहाड़ी और दूरदराज़ के क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
    - उड़ान योजना का चरण 4 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें द्वीपों और देश के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
    - चरण 5 को अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसमें श्रेणी-2 (20-80 सीटें) और श्रेणी-3 (>80 सीटें) विमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें उड़ान के मूल तथा गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

उत्तराखंड में बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने राज्य में 33 बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये 559 करोड़ रुपए जारी किये।

मुख्य बिंदु:

- वित्त मंत्रालय के सहायक निदेशक के एक पत्र में कहा गया है कि यह राशि राज्य के लिये 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2023-24' के भाग- I के तहत अतिरिक्त आवंटन के हिस्से के रूप में दी गई है।
    - केम्प्टी फॉल के लोकप्रिय पर्यटन स्थल के पास एक सुरंग पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिये 26 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    - देहरादून के बाहरी इलाके हरबर्टपुर में एक अंतर-राज्य बस टर्मिनल के विकास के लिये 10.8 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
    - मसूरी में मॉल रोड के अग्रभाग को बेहतर बनाने के लिये 17 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जबकि पुलिस बल को मज़बूत करने के लिये 20 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    - हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जबकि देहरादून में शौर्य स्थल के निर्माण के लिये 51 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
    - सोंग बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिये 88 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं तथा उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पुलिस के लिये आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

नोट :

पूंजी निवेश योजना के लिये राज्यों को विशेष सहायता

- पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष सहायता की योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र शुरू की गई थी।
- वर्तमान में इस योजना का विस्तार किया गया है तथा इसे 1.3 लाख करोड़ रुपय के आवंटन के साथ 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2023-24' के रूप में जारी रखा गया है।

जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर पेड़ों की कटाई और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों में शामिल होने के लिये उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई।

मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एक समिति इस बात पर गौर करेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर या सीमांत क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति दी जा सकती है।

नोट :

- शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को पर्यावरण को होने वाली हानि को कम करने के उपायों का प्रस्ताव देने और जवाबदेह लोगों से क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिये एक समिति स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने टाइगर रिज़र्व में पेड़ों की अभूतपूर्व कटाई और पर्यावरणीय क्षति पर सरकार की खिंचाई की। इसमें जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण, पेड़ों की कटाई पर तीन महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
- इससे पहले जनवरी में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर बाघ सफारी स्थापित करने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें "पर्यटन-केंद्रित" दृष्टिकोण के बजाय "पशु-केंद्रित" दृष्टिकोण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था।
- न्यायालय का रुख राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर वन्यजीवों के कल्याण और संरक्षण को प्राथमिकता देने के महत्त्व को रेखांकित करता है, जो पर्यटकों के आकर्षण पर पशुओं के लिये प्राकृतिक आवास बनाए रखने के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

- यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में अवस्थित है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान) में हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का एक हिस्सा है।
  - इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था।
  - इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जबकि बफर ज़ोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- रिज़र्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है।
- रामगंगा, सोननदी, मंडल, पालेन और कोसी, रिज़र्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं।
- 500 वर्ग किलोमीटर में फैला CTR 230 बाघों का वास-स्थान है और प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में 14 बाघों के साथ यह दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिज़र्व है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के साथ की गई थी।
- बाघ संरक्षण के सशक्तीकरण के लिये वर्ष 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत इसे गठित किया गया था।

उत्तराखंड हिमालय में तेज़ी से बढ़ती हिमनदीय झील को लेकर चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) के वैज्ञानिकों के अनुसार भागीरथी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित भिलंगना हिमनद झील पिछले 47 वर्षों में लगभग 0.38 वर्ग किमी. तक विस्तारित हुई है जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये संभावित खतरा उत्पन्न कर सकती है।

प्रमुख बिंदु

- हिमनद झील का निर्माण तब होता है जब हिमनदों की विशाल चादर पिघलने लगती है और पिघला हुआ जल एकत्रित हो जाता है।
  - वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन में तीव्रता के साथ ही कई हिमनद भी तेज़ी से पीछे हटने लगे हैं, जिससे कई ऐसी हिमनद झीलों का निर्माण शुरू हो गया है, इनकी अस्थिरता के कारण जल की तेज़ धार नीचे की ओर प्रवाहित हो सकती हैं जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।

- अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तराखंड हिमालय में एक हज़ार से अधिक ऐसी हिमनद झीलें बनी हैं, लेकिन पर्याप्त भूमि-आधारित अध्ययनों की कमी के कारण उनके संबंध में जानकारी सीमित है।
  - उत्तराखंड में 13 ऐसी हिमनद झीलों की पहचान की गई है जो मोराइन डैम्ड लेक हैं और लगभग दस हिमनद हैं जिनकी निचले भाग में रहने वाले लोगों के लिये संभावित खतरे को देखते हुए निरंतर निगरानी की जा रही है।
  - ऐसा ही अनुभव वर्ष 2013 में केदारनाथ में, वर्ष 2021 में ऋषिगंगा-धौलीगंगा हिमस्खलन में और हाल ही में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील में किया गया था।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अनुसार, भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग 9,575 हिमनद हैं, उनमें से केवल 980 उत्तर-पश्चिमी राज्य उत्तराखंड में हैं तथा सबसे संवेदनशील हिमनदों का विशेषज्ञ टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। .
- उत्तराखंड हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद, गंगोत्री हिमनद, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है, प्रति वर्ष लगभग 15-20 मीटर की दर से पीछे हट रहा है।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG)

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- जून, 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के दो कमरों में एक छोटे केंद्र के रूप में स्थापित इस संस्थान को अप्रैल, 1976 के दौरान देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)

- यह एक प्रकार की विनाशकारी बाढ़ है, जो हिमनद झील वाले बाँध विफल होने की स्थिति में, जिससे बड़ी मात्रा में जल निष्काषित होता है, में घटित होती है।
- इस प्रकार की बाढ़ आम तौर पर हिमनदों के तेज़ी से पिघलने अथवा भारी वर्षा या पिघले जल के प्रवाह के कारण झील में जल के संचय के कारण होती है।
- फरवरी 2021 में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ आई, जिसके बारे में संभावना जताई जाती है कि यह ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण हुई थी।
- **कारण:**
  - इस प्रकार के बाढ़ आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हिमनद के घनत्त्व में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन तथा भूकंप शामिल हैं।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से कई नए हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है, जो GLOF का प्रमुख कारण हैं।

मोराइन डैम्ड लेक

- मोराइन डैम्ड लेक का निर्माण तब होता है जब टर्मिनल मोराइन के कारण कुछ पिघले जल घाटी से बाहर नहीं निकल पाते हैं।
- जब कोई हिमनद पीछे की ओर हटता है, तब पीछे हटने वाले हिमनद तथा बचे हुए टुकड़े के बीच एक जगह बच जाती है, जिसमें बचा हुआ मलबा (मोराइन) बचता है।
- बर्फ के पिघलने के पैटर्न के कारण दोनों हिमनदों से पिघला हुआ जल इस स्थान में रिसकर एक रिबन के आकार की झील का निर्माण करता है।
- इस बर्फ के पिघलने से हिमनद झील में बाढ़ आ सकती है, जिससे पर्यावरण और आस-पास रहने वालों को गंभीर नुकसान हो सकता है।

उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भारत द्वारा सैनिकों की तैनाती पर विचार

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मज़बूत करने के लिये 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की है।

प्रमुख बिंदु:

- माना जा रहा है कि इन सैनिकों को उत्तरी राज्यों; उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण 532 किमी. (330.57 मील) हिस्से की सुरक्षा के लिये तैनात किया जाएगा।
- सैनिकों की इस प्रकार की तैनाती इस क्षेत्र के सामरिक महत्त्व एवं भारत के नेताओं की नज़र में इसकी बढ़ती संवेदनशीलता दोनों को उजागर करती है।
- पिछले दशक में इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश और विकास देखा गया है।
- वर्ष 2020 में एक गंभीर सीमा संघर्ष के बाद, जिसमें पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में कम-से-कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, वर्ष 2021 में, भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा पर गश्त करने के लिये अतिरिक्त 50,000 सैनिकों को तैनात किया।

उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा की तैयारी के लिये समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी के लिये एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश भी दिये:
  - चारधाम मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर सीसीटीवी लगाया जाना।
  - सरकार के स्तर से सभी चारधामों की लाइव मॉनिटरिंग की जानी चाहिये तथा आपदा कन्ट्रोल रूम को सुचारु रूप से संचालित किया जाना चाहिये।
  - प्लास्टिक मुक्त चारधाम यात्रा सुनिश्चित करना।
  - सभी धामों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना। रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाए।
  - चिकित्सा एवं अपेक्षित स्टाफ की तैनाती के साथ-साथ यात्रा रास्तों पर अस्थायी चिकित्सा केंद्रों में जीवन रक्षक औषधियाँ, उपकरण, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेण्डर एवं एंबुलेंस/एयर एंबुलेंस की व्यवस्था।
  - घोड़ों एवं खच्चरों में बीमारियों की रोकथाम के लिये रास्तों पर पशु चिकित्सकों की तैनाती।
  - सुरक्षा बलों की तैनाती की व्यवस्था।
  - तीर्थयात्रा अवधि के दौरान यातायात प्रबंधन के लिये अतिरिक्त अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।

नोट:

- **यमुनोत्री धाम:**
  - स्थान: उत्तरकाशी ज़िला
  - को समर्पित: यमुना नदी देवी
  - गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है।
- **गंगोत्री धाम:**
  - स्थान: उत्तरकाशी ज़िला
  - को समर्पित: गंगा नदी देवी
  - सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र।
- **केदारनाथ धाम:**
  - स्थान: रुद्रप्रयाग ज़िला
  - को समर्पित: भगवान शिव

- यह मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है।
- भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।

- **बद्रीनाथ धाम:**
  - स्थान: चमोली ज़िला
  - पवित्र बद्रीनारायण मंदिर के लिये प्रसिद्द।
  - को समर्पित: भगवान विष्णु।
  - वैष्णवों के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक

उत्तराखंड ने 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू कीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वस्तुत: 8,275.51 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु:

- इनमें 11 विभागों की 1048.15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 15 विभागों की 7227.36 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
- सीएम ने ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर की शुरुआत की और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट वितरित किये।
- उन्होंने उद्यमियों और मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन पत्र वितरित किये।
- उत्तराखंड की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में, मुख्यमंत्री ने पाँच वर्षों के भीतर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करने की योजना की रूपरेखा तैयार की।
  - उन्होंने वर्ष 2025 तक ज़िला स्तर पर नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये रणनीतियों को स्पष्ट किया।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना

- उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना शुरू की।
- योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं तथा वापस आये प्रवासियों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किये जायेंगे।

उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिये सैकड़ों लोग आगे आए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सैकड़ों पुरुष, महिलाएँ और बच्चे उत्तराखंड के अल्मोडा ज़िले के पवित्र जागेश्वर धाम में क्षेत्र के प्रसिद्ध हिमालयी देवदार के पेड़ों (सेड्रस देवदार) के चारों ओर रक्षा सूत्र बाँधने के लिये एकत्र हुए।

मुख्य बिंदु:

- कुछ पेड़ 500 वर्ष से अधिक पुराने हैं और वे विश्व के एक परिसर के भीतर 125 मंदिरों के सबसे बड़े समूहों में से एक को घेरे हुए हैं, जो समुद्र तल से 1,870 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- राज्य सरकार के 'मानसखंड मंदिर माला मिशन' के तहत सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिये काटे जाने वाले 1,000 से अधिक पेड़ों पर रक्षा सूत्र बाँधा गया था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में लगभग 50 मंदिरों से कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
  - यह उत्तराखंड के जंगलों को तेज़ी से औद्योगीकरण के कारण बढ़ते विनाश से बचाने के लिये 1970 के दशक के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के समान है।

- यह पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार को जागेश्वर में विकास में सहायता के लिये पेड़ों की कथित रूप से लापरवाही से कटाई के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा है।
    - सितंबर 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा भवन उपनियम बनाए जाने तक मंदिर स्थल के आस-पास सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
        - उच्च न्यायालय ने जागेश्वर मंदिर परिसर के आस-पास "अनियोजित और अनधिकृत" निर्माण का स्वत: संज्ञान लेते हुए आरतोला-जागेश्वर सड़क के निर्माण को रोकने का भी आदेश दिया।

देवदार के पेड़

- सेड्रस देवदारा, जिसे सामान्यत: देवदार के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी हिमालय के मूल निवासी शंकुधारी वृक्ष की एक प्रजाति है। इसकी लकड़ी के लिये इसे अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है और इसकी सजावटी सुंदरता के लिये व्यापक रूप से इसकी कृषि की जाती है।
- ये पेड़ ठंडी जलवायु के लिये अनुकूलित होते हैं और अक्सर अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं।
- वे समशीतोष्ण और उप-जलवायु के लिये उपयुक्त हैं।
- देवदार का उपयोग अक्सर उनके आकर्षक, पिरामिड आकार के विकास और सुगंधित लकड़ी के कारण भूनिर्माण तथा पार्कों व बगीचों में सजावटी पेड़ों के रूप में किया जाता है।
- वे पक्षियों और छोटे स्तनधारियों सहित विभिन्न वन्यजीवों को आवास व भोजन प्रदान करते हैं।

मानसखंड मंदिर माला मिशन

- मानसखंड मंदिर मिशन के तहत सरकार मंदिरों के मार्गों पर बेहतर परिवहन सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर सड़कें भी विकसित करेगी।

नोट :

- अगले 25 वर्षों में इन मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के मार्गों पर होटल और होमस्टे सुविधाओं का विकास।
- मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत कुमाऊँ मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जाएगा।
- मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत निम्नलिखित मंदिरों की पहचान की गई है:
  - जागेश्वर महादेव मंदिर, अल्मोडा
  - चितई गोलू मंदिर
  - सूर्यदेव मंदिर कटारमल,
  - कसार देवी मंदिर
  - नंदा देवी मंदिर
  - पाताल भुवनेश्वर मंदिर, पिथोरागढ़
  - हाट कालिका मंदिर
  - बागनाथ मंदिर, बागेश्वर
  - बैजनाथ मंदिर
  - चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर
  - माँ पूर्णागिरि मंदिर
  - माँ बाराही देवी मंदिर
  - बालेश्वर मंदिर
  - नैना देवी मंदिर, नैनीताल
  - उधम सिंह नगर में कैंची धाम मंदिर और चैती धाम मंदिर

चिपको आंदोलन

- यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले (अब उत्तराखंड) में शुरू हुआ था।
- इस आंदोलन का नाम 'चिपको' 'वृक्षों के आलिंगन' के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिये उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया।
- जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिये इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया।
- इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा यह समझाना था कैसे ज़मीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है।
- इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1,000 msl (माध्य समुद्र तल-msl) से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया।

उत्तराखंड ने रोज़गारोन्मुख उद्योगों के लिये सब्सिडी की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोज़गारोन्मुखी उद्योग स्थापित करने के लिये 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए और मैदानी इलाकों के लिये 100 करोड़ रुपए रखी गई है।
- इस नीति के तहत स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों को कुल लागत का 25% या अधिकतम 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

- प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सब्सिडी पाँच चरणों में दी जाएगी।
- यह नीति राज्य में 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी।
- अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस का लाभ लेने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति को स्वीकृति दी गई है।
- कैबिनेट ने हर्रावाला में कैंसर अस्पताल और मातृ-शिशु चिकित्सा संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से संचालित करने की भी स्वीकृति दे दी है।
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों को 5000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

- यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
  - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं तथा निदान की लागत शामिल है।

एशियाई विकास बैंक ने टिहरी में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी ज़िले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये 1,294 करोड़ रुपए की फंडिंग को स्वीकृति दी है।

मुख्य बिंदु:

- इन परियोजनाओं को 80:20 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें ADB 80% व्यय वहन करेगा और उत्तराखंड सरकार 20% व्यय वहन करेगी।
- टिहरी में निर्दिष्ट क्षेत्रों के टिकाऊ, समावेशी और जलवायु लचीले पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु, राज्य सरकार ने टिहरी बाँध जलाशय तथा आसपास के क्षेत्रों को एक विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया।
  - जिसके बाद टेहरी विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम, 2013 के तहत टेहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (टाडा) की स्थापना की गई।
  - इसके बाद भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परामर्श की एक श्रृंखला और ADB को प्रस्ताव दिये गए, जो अब पूरे प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये एक परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में फलीभूत हो गया है।
  - प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिये सात परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें शामिल हैं:
- कोटी कॉलोनी से डोबरा चांठी पुल तक 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क जिसमें समर्पित साइक्लिंग ट्रैक, व्यू प्वाइंट और समर्पित हॉकर क्षेत्र होगा।
  - कोटि कॉलोनी से तिवार गाँव तक 450 मीटर काँच के तले वाला पैदल यात्री झूला पुल,
  - डोबरा-चांठी में एक सांस्कृतिक हाट और उत्तराखंड वास्तुकला थीम पार्क,
  - तिवार गाँव में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का उन्नयन और टिपरी-मदन नेगी में नई रोपवे परियोजना।
- इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन बुनियादी ढाँचे का विकास करना है, जिसमें हरित आवरण को बढ़ाने, आजीविका सृजन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व प्राकृतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में न्यूनतम व्यवधान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- परियोजना के लिये इंजीनियरों, वास्तुकारों, पर्यावरण विशेषज्ञों, लिंग विशेषज्ञों और सामुदायिक विशेषज्ञों सहित कुल 56 पद स्वीकृत किये गए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि विकासात्मक गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पर्यावरण व सामाजिक-सांस्कृतिक मानकों के अनुरूप हैं।
- समग्र परियोजना में मौसम निगरानी प्रणाली, पर्यावरण डेटा संग्रह और एक एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र की स्थापना जैसे हस्तक्षेपों के साथ स्मार्ट बुनियादी ढाँचे में सुधार भी शामिल होगा।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
  - इसमें 68 सदस्य हैं; 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- ADB सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है।
- 31 दिसंबर, 2022 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारक जापान और अमेरिका (प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%), चीन (6.4%), भारत (6.3%) तथा ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
- इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

उत्तराखंड में UCC को राष्ट्रपति की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के साथ कानून बन गया है।

- आज़ादी के बाद UCC अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 को अपनी सहमति दी।
- UCC सामाजिक समानता के महत्त्व को सिद्ध कर समरसता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- राज्य में इसके लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिला उत्पीड़न पर भी अंकुश लगेगा।

समान नागरिक संहिता

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
- ये निदेशक तत्त्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
  - UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता तथा विविधता के लिये खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।
- भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- शेष भारत अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है। शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

अनुच्छेद 201

- इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।
- राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिये राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है।

नोट :

गरतांग गली

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड में गरतांग गली का उपयोग भारत और तिब्बत के बीच रेशम मार्ग व्यापार मार्ग के रूप में किया जाता था।

मुख्य बिंदु:

- यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में नेलांग घाटी में स्थित है। यह एक अद्वितीय पर्यटक आकर्षण के रूप में भी खड़ा है।
- उत्तराखंड के सुदूर कोने में स्थित, गारतांग गली हलचल भरे पर्यटन सर्किट से दूर एक एकांत स्थान प्रदान करती है।
  - यह अनोखा स्थान प्रकृति के बीच प्रामाणिक अनुभव और शांति चाहने वाले यात्रियों को आकर्षित करता है।
  - गाँव में भोटिया जनजाति का निवास है, जो एक स्वदेशी समुदाय है जो अपनी लचीलापन, पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत के लिये जाना जाता है।
- गारतांग गली ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग था।
- व्यापारी इस पहाड़ी दर्रे से होकर गुज़रते थे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, विचारों और सांस्कृतिक प्रभावों के आदान-प्रदान में सुविधा होती थी।
- गरतांग गली चट्टान-किनारे लटकती सीढ़ी, जिसे गरतांग गली पुल के नाम से भी जाना जाता है, नेलांग नदी घाटी में 11,000 फीट की ऊँचाई पर एक ऊर्ध्वाधर रिज के साथ 500 मीटर तक फैला है।
  - इसका निर्माण पारंपरिक देशी शैली में शुरू में पेशावर के पठान व्यापारियों द्वारा किया गया था, जो तिब्बत और भारत के बीच सिल्क रोड व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता था।
  - वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, भारतीय सेना द्वारा पहुँच प्रतिबंधित कर दी गई, जिससे पुल जर्जर हो गया।
  - वर्ष 2015 में भारत द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटन के लिये फिर से खोलने के बाद, पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके लकड़ी की सीढ़ी को बहाल करने के प्रयास किये गए।
  - 59 वर्षों के बाद, पुल को अगस्त 2021 में जनता के लिये फिर से खोल दिया गया।

रेशम मार्ग

- यह प्राचीन वाणिज्यिक मार्गों का एक नेटवर्क था जो पूर्व और पश्चिम को चीन से भूमध्य सागर तक जोड़ता था तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करता था।
- हान युग (207 ईसा पूर्व - 220 सीई) की शुरुआत में पूरे देश में चीनी रेशम के बढ़ते व्यापार ने "सिल्क रोड" शब्द को जन्म दिया। 114 ईसा पूर्व के आसपास, हान राजवंश ने मध्य एशिया के माध्यम से व्यापार मार्गों का विस्तार किया, मुख्य रूप से एक चीनी शाही दूत झांग कियान की यात्रा और मिशन के परिणामस्वरूप।
- सिल्क रोड के साथ व्यापार के परिणामस्वरूप, चीन, भारतीय उपमहाद्वीप, फारस, यूरोप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब की सभ्यताओं के बीच लंबी दूरी के राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध स्थापित हुए।
- यद्यपि रेशम निस्संदेह चीन से मुख्य निर्यात था, रेशम मार्गों में कई अन्य वस्तुओं के साथ-साथ समन्वित विचारों, कई प्रौद्योगिकी, धर्मों और रोगों का आदान-प्रदान भी हुआ। सिल्क रोड का उपयोग सभ्यताओं द्वारा वाणिज्यिक व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के लिये किया जाता था।

भोटिया जनजाति

- भोटिया या भोटिया चरवाहों की एक व्यावसायिक जाति है।
- उत्तराखंड के भोटिया लोग तीन सीमावर्ती ज़िलों-पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में सात मुख्य नदी घाटियों में फैले हुए हैं।
- उत्तराखंड में सात प्रमुख भोटिया समूह हैं जोहारी, दरमिया, चौदांसी, ब्यांसी, मार्छा (माना घाटी), तोल्छा (नीती घाटी) और जाध।

उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन पंचायतों को मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में, उत्तराखंड सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत ब्रिटिश काल के 'वन पंचायत के अधिनियमों' में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- नए नियमों के अनुसार नौ सदस्यीय वन पंचायत बनाई जाएगी, जिसे जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वनाग्नि रोकथाम, इको-पर्यटन में भाग लेने का अधिकार होगा।
- पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी जोड़ा गया है।
  - वन पंचायत की अवधारणा - कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदायों द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में शुरू की गई।
- उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ वन पंचायत प्रणाली लागू है।
  - यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है।
  - वर्तमान में राज्य में 11,217 वन पंचायतें हैं जिनमें 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है।
- कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पुरानी डीज़ल ईंधन वाली बसों और थ्री व्हीलर टेम्पो से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 'उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी' को स्वीकृति दे दी।
  - यह नीति सबसे पहले देहरादून में लागू की जाएगी और उसके बाद अन्य ज़िलों में विस्तारित की जाएगी।

उत्तराखंड ने गोपेश्वर में विकास योजनाएँ शुरू कीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 229.3 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु:

- जनपद चमोली के पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित 'लाभार्थी सम्मान समारोह' में विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया।
  - इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ज़िले के विकास के लिये कई घोषणाएँ भी कीं, जिनमें शामिल हैं:
  - हापला-धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु
  - बैतरनी-सिरखोमा-सेंटुना-बैरागना मोटर मार्ग के किलोमीटर एक से दशोली ब्लॉक में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से सेतुना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासन एवं वित्तीय स्वीकृति,
  - कर्णप्रयाग में लामबगड़ के अंतर्गत गंगानगर माई मंदिर से भैरव टोक तक रामगंगा नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण,
  - थराली विधानसभा में चार विकास खंडों में गौ-संरक्षण सेवा की स्थापना एवं जनहित में थराली कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री ने अटल आवास योजना के तहत निर्मित आवासों के लाभार्थियों को चाबियाँ भी सौंपी।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नीलम देवी को दूसरी किस्त के तहत 60 हज़ार का चेक दिया गया।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संगीता देवी एवं गुड्डी देवी को आवास की चाबी दी गयी।
- मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के तहत राजेश्वरी देवी एवं नरेंद्र सिंह को 50-50 हज़ार रुपए की सहयोग राशि के चेक दिये गए।
- महिला सशक्तीकरण के तहत मंदोदरी देवी को महालक्ष्मी किट दी गई।
  - उल्लेखनीय कार्य के लिये युवक मंगल दल बूरा को 75,000 रुपए तथा महिला मंगल दल अला जोखना को 37,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक दिये गए।
  - देवभूमि मत्स्य जीवी सहकारिता समिति को 20 लाख रुपए का चेक दिया गया।

नोट :

उत्तराखंड के मोटे अनाज के किसानों की आय में वृद्धि: अध्ययन

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर के एक अध्ययन के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कदन्न की कृषि को बढ़ावा देने के कारण उत्तराखंड में कदन्न उगाने वाले चार में से तीन किसानों की वार्षिक आय में 10-20% की वृद्धि देखी गई है।

इस अध्ययन को "उत्तराखंड में कदन्न के उत्पादन: इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और विपणन चुनौतियों का एक अनुभवजन्य विश्लेषण" नाम दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- 2,100 से अधिक किसानों पर किये गए अध्ययन में पाया गया कि उनमें से कई अभी भी कदन्न-आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग से अवगत नहीं हैं और अभी भी इसे केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिये छोटे पैमाने पर उगा रहे हैं।

इस अध्ययन के अनुसार, राज्य में कदन्न उगाने वाले 75% किसानों की आय में 10-20% की वृद्धि देखी गई है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार इस फसल की कृषि को बढ़ावा दे रही है।

  - हालाँकि अध्ययन में सर्वेक्षण में शामिल 2,100 किसानों में से कदन्न उगाने वाले किसानों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।
  - इसे छह महीने की अवधि में संस्थान के चार वरिष्ठ प्रोफेसर और पाँच डेटा संग्रहकर्त्ताओं द्वारा संचालित किया गया था।
- यह अध्ययन कदन्न उत्पादन की विपणन क्षमता की चुनौतियों का समाधान करने और इसकी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के लिये प्रभावी रणनीतियों की पहचान करने हेतु आयोजित किया गया था।
  - सर्वेक्षण के लिये नमूना आकार राज्य के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों से एकत्र किया गया था, जिसमें पिथौरागढ़, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल हैं।

सरकार द्वारा की गई संबंधित पहल

- राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन (NMM): कदन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2007 में एनएमएम शुरू किया गया था।
- मूल्य समर्थन योजना (PSS): कदन्न की कृषि के लिये किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास: कदन्न की मांग और खपत बढ़ाने के लिये मूल्यवर्धित कदन्न-आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- PDS में कदन को बढ़ावा देना: सरकार ने इसे जनता के लिये सुलभ और किफायती बनाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदन्न प्रस्तुत किया है।
- जैविक खेती को बढ़ावा: जैविक कदन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिये सरकार कदन्न की जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है।

उत्तराखंड में बुनियादी ढाँचे के विकास को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने शैक्षिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये उत्तराखंड सरकार को 101.27 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- शैक्षणिक संस्थान 1,05,818 लाख आबादी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जिनमें से 25% से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।
- छात्रों की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा के दौरान समावेशी और समग्र बुनियादी ढाँचे के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, MoMA ने कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है।
- ये सुविधाएँ उच्च शिक्षा के महत्त्व को दर्शाती हैं, जिससे विश्लेषणात्मक मानसिकता, कौशल विकास, कैरियर उन्नति आदि के विकास में उच्च शिक्षा का योगदान होता है, जिससे राज्य के युवाओं का शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास होता है।

अल्पसंख्यकों के लिये संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 29:
  - इसमें प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे उसको संरक्षित करने का अधिकार होगा।
  - यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद का दायरा आवश्यक रूप से केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में 'नागरिकों का वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 30:
  - सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
  - अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है (अनुच्छेद 29 के तहत)।
- अनुच्छेद 350-B:
  - 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 1956 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
  - संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करना विशेष अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का गृह सचिव नियुक्त किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने IAS अधिकारी दिलीप जावलकर को नया गृह सचिव नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में वित्त सचिव के पद पर कार्यरत दिलीप जावलकर को उत्तराखंड में गृह सचिव की ज़िम्मेदारी संभालने के लिये चुना गया है।
- निर्वाचन आयोग के निर्देश ने आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान हितों के संभावित टकराव को रोकने के उद्देश्य से संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालयों में समवर्ती पदों पर रहने वाले गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया।

अधिकारियों ने जोशीमठ में सरकारी भवनों को रेड ज़ोन से स्थानांतरित करने को कहा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चमोली के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) ने अधिकारियों से भूमि धंसाव प्रभावित जोशीमठ में असुरक्षित रेड ज़ोन में सरकारी भवनों और संपत्तियों का सर्वेक्षण करने तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिये कहा।

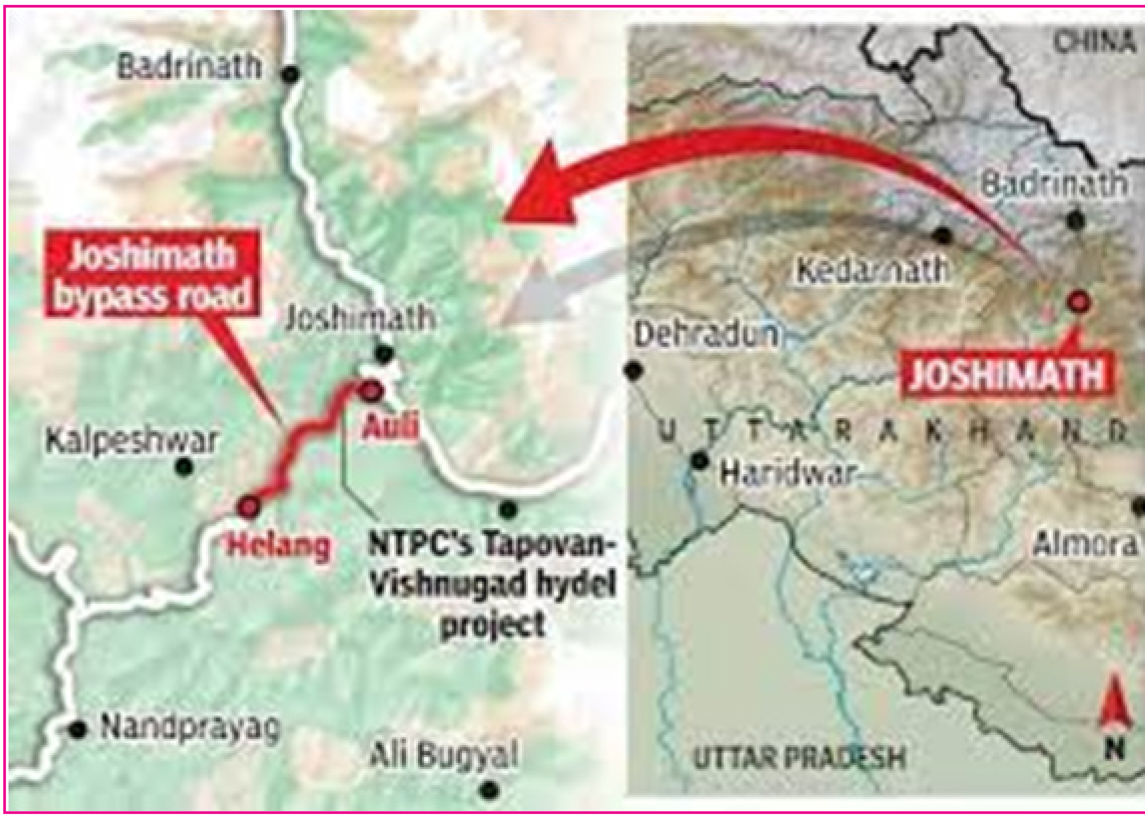

मुख्य बिंदु:

- DM ने अधिकारियों से जोशीमठ में रेड ज़ोन के अंतर्गत आने वाले भूस्खलन प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के सभी विकल्प प्रदान करने को भी कहा।
- जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति और जोशीमठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ने राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का विरोध किया है तथा 15 मांगें रखी हैं, जिनमें जोशीमठ में भूमि धँसाव की समस्या के लिये उपचारात्मक उपाय शुरू करना व प्रभावित लोगों के लिये विस्थापन भत्ता शामिल है।

जोशीमठ

- जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-7) पर स्थित एक पहाड़ी शहर है।

नोट :

- राज्य के अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी (Valley of Flowers) एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है।
- जोशीमठ, जो सेना की सबसे महत्त्वपूर्ण छावनियों में से एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिये अत्यधिक सामरिक महत्त्व रखता है।
- शहर (उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र-V) के माध्यम से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम, विष्णुप्रयाग से एक उच्च ढाल के साथ बहती हुई धारा आती है।
- यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मुख्य मठों में से एक है, अन्य मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोशीमठ, ओडिशा के पुरी और कर्नाटक के श्रींगेरी में हैं।

जोशीमठ की समस्याओं का कारण:

- पृष्ठभूमि:
  - दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार वर्ष 2021 में दर्ज की गई, जबकि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भूस्खलन एवं बाढ़ की घटनाएँ निरंतर रूप से देखी जा रही थीं।
  - रिपोर्टों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने वर्ष 2022 में पाया कि जोशीमठ के कई हिस्सों में मानव निर्मित और प्राकृतिक कारकों के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है।
  - यह पाया गया कि व्यावहारिक रूप से शहर के सभी ज़िलों में संरचनात्मक खामियाँ हैं और अंतर्निहित सामग्री के नुकसान या गतिविधियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह के धीरे-धीरे या अचानक धँसने अथवा विलय हो जाने जैसे परिणाम देखने को मिलते रहने की संभावना है।
- कारण:
  - एक प्राचीन भूस्खलन स्थल: वर्ष 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जोशीमठ मुख्य चट्टान पर नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। यह एक प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकनंदा एवं धौलीगंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव भी भूस्खलन के कारकों के अंतर्गत आते हैं।
    - समिति ने भारी निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत के लिये बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
  - भौगोलिक स्थिति: क्षेत्र में बिखरी हुई चट्टानें पुराने भूस्खलन के मलबे जिसमें बाउलडर, नीस चट्टानें और ढीली मृदा शामिल है, से ढकी हुई हैं, जिनकी धारण क्षमता न्यून है।
  - ये नीस चट्टानें अत्यधिक अपक्षयित प्रकृति की होती हैं और विशेष रूप से मानसून के दौरान पानी से संतृप्त होने पर इनके रंध्रों पर उच्च दबाव बन जाता है फलस्वरूप इनका संयोजी मूल्य कम हो जाता है।
  - निर्माण गतिविधियाँ: निर्माण कार्य में वृद्धि, पनबिजली परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है।
  - भू-क्षरण: विष्णुप्रयाग से बहने वाली धाराओं और प्राकृतिक धाराओं के साथ हो रहा चट्टानी फिसलन, शहर में भूस्खलन के अन्य कारण हैं।
- प्रभाव:
  - कम-से-कम 66 परिवारों ने शहर छोड़ दिया है, जबकि 561 घरों में दरारें आने की सूचना है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

उत्तराखंड में ग्लोबल फेस्ट में 700 से अधिक योग विशेषज्ञों ने भाग लिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश-विदेश से 700 से अधिक योग विशेषज्ञों और अभ्यासकर्त्ताओं ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक सप्ताह तक चलने वाले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग लिया।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा आयोजित यह महोत्सव मुनि-की-रेती में योग भारत गंगा घाट पर आयोजित किया गया था।
- राज्य सरकार भारत और विदेशों में योग के प्रति उत्साही लोगों, प्रशिक्षकों, विशेषज्ञों तथा छात्रों के लिये एक साझा मंच प्रदान करने के इरादे से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को बढ़ावा दे रही है। ऋषिकेश वैश्विक योग राजधानी बन गया है और यह महोत्सव इसे आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, ईशा फाउंडेशन, शिवानंद आश्रम, मानव धर्म आश्रम और कृष्णमाचार्य योग मंदिरम जैसे योग एवं धार्मिक संस्थानों ने भी उत्सव में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY)

- यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। IDY का विचार भारत द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
- वर्ष 2015 में नई दिल्ली के राजपथ पर पहले योग दिवस समारोह ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।

उत्तराखंड की उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पाँच हिमनद झीलों का जोखिम मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की दो टीमों का गठन किया है, जो "बाढ़ के प्रकोप" के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रस्तावित किया गया है कि टीमें, मई-जून 2024 में इन झीलों पर अपना काम शुरू कर देंगी।
- हिमालयी राज्यों की 188 हिमनद झीलों में से 13 उत्तराखंड में स्थित हैं।
- फरवरी 2021 में उत्तराखंड में चमोली ज़िले में एक हिमनद झील का विस्फोट हुआ, जिससे ऋषिगंगा पर एक छोटी जल विद्युत परियोजना बह गई तथा अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई।
- उत्तराखंड की 13 हिमनद झीलों को 'ए', 'बी' एवं 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 'ए' अत्यधिक संवेदनशील है।
  - उत्तराखंड में 13 हिमनद झीलों में से श्रेणी 'ए' में पाँच (अत्यधिक संवेदनशील), श्रेणी 'बी' में चार, (संवेदनशील) और श्रेणी 'सी' में चार (अपेक्षाकृत कम संवेदनशील) आती हैं।
    - पाँच अति संवेदनशील झीलों में से चार पिथौरागढ ज़िले में और एक चमोली में है तथा चार संवेदनशील झीलों में से दो पिथौरागढ में एवं एक-एक चमोली व टिहरी में है।
- पहली टीम में दो हिमनदी झीलों की संवेदनशीलता का आकलन राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के विशेषज्ञ शामिल थे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, लखनऊ, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा उत्तराखंड भूस्खलन शमन एवं प्रबंधन केंद्र करेगा।
  - पहले चरण के कार्य में उपग्रह डेटा अध्ययन एवं डेटा संग्रह, बैथिमेट्री और क्षेत्र सर्वेक्षण सम्मिलित होगा।
- दूसरी टीम का नेतृत्व, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC), पुणे, प्रमुख तकनीकी एजेंसी के रूप में कर रही है तथा इसमें देहरादून स्थित भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान सम्मिलित है | वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा उत्तराखंड भूस्खलन शमन एवं प्रबंधन केंद्र 'ए' श्रेणी में आने वाली अन्य तीन हिमनद झीलों का अध्ययन व सर्वेक्षण करेगा।

भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान

- यह प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग, जियोइन्फॉर्मेटिक्स और जीपीएस तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है।
- इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग के तहत की गई थी।

- यह देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)

- यह एक प्रकार की विनाशकारी बाढ़ है, जो हिमनद झील वाला बाँध के टूट जाने से आती है जिससे अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है।
- इस प्रकार की बाढ़ सामान्यत: ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने या भारी वर्षा या पिघले पानी के प्रवाह के कारण झील में पानी के संचय के कारण होती है।
- फरवरी 2021 में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ देखी गई, जिसके बारे में संदेह है कि यह GLOF के कारण हुई थी।

कारण:

- ये बाढ़ कई कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें ग्लेशियर की मात्रा में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन एवं भूकंप शामिल हैं।
- NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से कई नए हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है, जो GLOF का प्रमुख कारण हैं।

उत्तराखंड चार बाघों को राजस्थान स्थानांतरित करेगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अधिकारियों के अनुरोध के बाद उत्तराखंड सरकार चार बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई है।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्थान भेजे जाने वाले बाघों को संरक्षित वन क्षेत्र से नहीं बल्कि बफर ज़ोन से पकड़ा जाएगा।
  - तीन बाघों को ओडिशा में स्थानांतरित करने का एक समान अनुरोध भी प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन है।
- उत्तराखंड में बाघ पुनर्वास परियोजना के सफल संचालन के बाद राजस्थान और ओडिशा सरकारों से बाघों के स्थानांतरण के लिये अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके तहत चार बड़ी बिल्लियों को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व से राजाजी टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया था।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार, बाघ संरक्षण को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2006 में संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।

राजाजी टाइगर रिज़र्व

- यह हरिद्वार (उत्तराखंड) में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।
- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में उत्तराखंड में तीन अभयारण्यों यानी राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर की गई थी।
- इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी. राजगोपालाचारी लोकप्रिय रूप से "राजाजी" के नाम से जाने जाते हैं, के नाम पर रखा गया था।
- इसे वर्ष 2015 में देश का 48वाँ बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।

भारतीय रेलवे और उत्तराखंड पर्यटन ने लॉन्च की मानसखंड एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) के साथ मिलकर, उत्तराखंड में कुमाऊँ क्षेत्र के छिपे हुए रत्नों को बढ़ावा देने के लिये "मानसखंड एक्सप्रेस" नामक एक नई पर्यटक ट्रेन शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- "मानसखंड एक्सप्रेस - भारत गौरव पर्यटक ट्रेन" 10 रातों/11 दिनों की एक विशेष यात्रा है।
- यह अनूठी यात्रा अपने आध्यात्मिक महत्त्व और विरासत स्थलों के लिये मशहूर देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य सुंदरता तथा सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिये बनाई गई है।
- 22 अप्रैल, 2024 को प्रस्थान करने वाली यह यात्रा पूरे उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों की व्यापक खोज प्रदान करती है।
  - ट्रेन के बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशनों में पुणे, लोनावाला, पनवेल, कल्याण, नासिक, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारासी तथा रानी कमलापति शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के लिये पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
  - यात्रा के कुछ मुख्य आकर्षणों में बालेश्वर, चाय बागानों और मायावती आश्रम का पता लगाने के लिये चंपावत/लोहाघाट का दौरा, नंदा देवी तथा कैंची धाम- बाबा नीम करोली मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करना एवं नानकमत्ता गुरुद्वारा- खटीमा व नैना देवी- नैनीताल में आशीर्वाद लेना शामिल है।
  - इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को जागेश्वर धाम और गोलू देवता - चितई की आध्यात्मिक आभा की खोज करने तथा हाट कालिका मंदिर एवं पाताल भुवनेश्वर की यात्रा करने का मौका मिलेगा।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :